

आम बजट 2021-22 • शहर के कारोबारियों और टैक्स माहिरों ने केंद्रीय बजट पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की

इनकम टैक्स में नई छूट नहीं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हाथ भी खाली

लुधियाना | सोमवार को घोषित किए गए आम बजट 2021-22 में आयकर दाताओं के लिए कोई नई रियायत नहीं दी गई। केवल 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। आम बजट को लेकर साइकिल इंडस्ट्री का कहना है कि वायु प्रदूषण को रोकना है तो इसके लिए निर्धारित बजट का कुछ हिस्सा साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। साइकिलिंग टैक विकसित किए जाने चाहिए। कारोबारियों और टैक्स माहिरों ने आम बजट पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। ऑटो पार्ट्स, कपड़ों, रॉ कॉटन, मोबाइल, विदेशी शराब पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी, सोना-चांदी में टैक्स में छूट भी अच्छा फैसला है।

स्टार्टअप, कम लागत वाली आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने से निवेश को मिलेगा बढ़ावा

75 साल से अधिक आयु वाले नाममात्र आयकरदाता हैं। नए बजट में 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले पेंशन भोगी को स्पेसिफाइड सीनियर



सिटीजन कहा जाएगा और इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट मिलेगी।

जिस बैंक खाते में उसे पेंशन प्राप्त हो रही है उसी बैंक में उसे डिक्लैरेशन फॉर्म जमा करवाना होगा।
-जतिंदर खुराना, प्रदेश प्रभान, इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन

42 शहरी केंद्रों को पर्यावरणीय चिंता को दूर करने में मदद करने के लिए 2,217 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। यह स्वागत योग्य कदम है। हम आशा करते हैं कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इन निधियों का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल माध्यम के रूप में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए हो।



-पंकज मुंजाल, चेयरमैन व एमडी, एचएमसी

स्टार्टअप, कम लागत वाली आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मूल्यांकन की समय अवधि में कमी से राहत मिलेगी। सड़क-रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास, हेल्थ केयर, जल आपूर्ति, स्वच्छ वायु, आरएंडडी, एमएसएमई के लिए आवंटन में वृद्धि का स्वागत करते हैं।
-गुरमीत सिंह कुलार, प्रेसिडेंट, फोको



यात्रा-पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। एयरलाइंस का निजीकरण, रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का आवंटन और नई राजमार्ग परियोजनाओं



का विकास अर्थव्यवस्था को नए विकास पथ पर ले जाएगा। हालांकि, यात्रा और

हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के लिए भी कुछ उम्मीदें थीं जैसे हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री का दर्जा देना, जीएसटी दर को कम करना जो संबंधित नहीं किए गए हैं।
-सोनिका मल्होत्रा कंधारी, जेएमडी, एमबीडी समूह

सभी एमएसएमई के लिए आवंटन को कम किया गया। सरकार ने स्किल इंडिया का नारा लगाया, लेकिन



स्किल का बजट विकास मंत्रालय 3002 करोड़ से घटकर 2785 हो गया है। यह विकासशील से अ विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में बदल सकता है।
-बादीश जिंदल, प्रेसिडेंट एआईटीएफ

75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पेंशन और ब्याज से इनकम है, उनको टैक्स रिटर्न भरने में छूट देना, हेल्थ बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़, स्टार्टअप के लिए 1 साल के लिए अतिरिक्त टैक्स से छूट स्वागत योग्य कदम है।
-राजश अग्रवाल, सीए

